आतंक का अट्टहास

शांति किसे नहीं सुहाती। लेकिन मौत के कुछ सौदागरों को दुनिया का अमन-चैन रास नहीं आता है। अपने वैश्विक रणनीतिक-कूटनीतिक हितों की पूर्ति के लिए वे ऐसी चाल चलते रहते हैं जिससे आतंक का रक्तबीज पनपता रहता है और दुनिया को भय और दशहत के साए में जीने को अभिशप्त होना पड़ता है। ये आतंक का दानव जब किसी देश को अपना निशाना बनाता है तो उसकी निर्माता महाशक्तियां उसे धैर्य और शांति रखने का उपदेश देती नजर आती हैं, लेकिन जब बात अपने पर आती है तो ये एक जुट होकर पूरी दुनिया से इस आतंक के रक्तबीज के संहार का आह्वान करते हैं। वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की महाताकतों द्वारा चलाए जा रहे अभियान का यह विरोधाभास बड़ी विडंबना है।

आतंक का क्रूर राक्षस महाशक्ति देशों से भरपूर खाद और पानी पाकर अब अट्टहास कर रहा है। मानों पूरी दुनिया को लील लेने को आतुर है। शायद ही कोई देश हो जो उससे खुद को सुरक्षित होने का दावा करने की स्थिति में हो। समय-समय पर वैश्विक आतंक के इस राक्षस को खत्म करने के अभियान भी चले। लेकिन पश्चिमी देशों के जादू से यह चोला बदलकर नए नाम से फिर दुनिया के सामने प्रकट होता रहा। अब इसका नया अवतार इस्लामिक स्टेट (आइएस) है। पेरिस में भीषण आतंकी हमले और रूसी विमान को मार गिराने के बाद इसे नेस्तनाबूद करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। फ्रांस सभी देशों से एकजुट होने की गुहार करता दिख रहा है। चूंकि सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य देशों को आइएस ने घाव दिया है तो बहुत संभव है कि इस संगठन के खिलाफ सभी लामबंद हो जाएं। समस्या तो भारत जैसे उन देशों के लिए है जो आतंक से पीड़ित हैं लेकिन आतंक के खिलाफ वैश्विक मुहिम में उनकी भूमिका तय नहीं है। उनके ऊपर आतंकी हमले कभी महाशक्ति देशों की प्राथमिकता में नहीं होते।

पेरिस में हुआ हमला मुंबई में हुए हमले जैसा था। अंतर सिर्फ यह है कि पेरिस हमले के तुरंत बाद फ्रांस ने आइएस के खिलाफ बम बरसाने शुरू कर दिए और विश्व बिरादरी ने इसका समर्थन किया। और एक हम हैं जिसे यह पता है कि मुंबई पर हमला (अन्य आतंकी हमले भी) किसने किया, किसकी शह पर किया, कौन-कौन शामिल था लेकिन हम सुबूतों को भेजने में जुटे हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मुहिम की यही सबसे बड़ी विसंगति है। कमियां सिर्फ गैरों में ही नहीं हैं, अपने भी कम दोषी नहीं हैं। किसी अन्य देश में आतंकी हमला होता है तो सभी देशवासी, राजनेता एक सुर में दोषियों को दंड देने की बात करते हैं। हमारे यहां तो क्षुद्र स्वार्थ वाली वोटबैंक की राजनीति के चलते आतंक के अलग-अलग रूप-रंग तय किए जाने लगते हैं। जो कहीं न कहीं आतंक के खिलाफ उठाए जाने वाले कदम, जनसमर्थन और इच्छाशक्ति को कुंद करते हैं। ऐसे में पेरिस में हुए आतंकी हमले के आलोक में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मुहिम में भारत की स्थिति की पड़ताल आज बड़ा मुद्दा है।

6 सर्वाधिक भुक्तभोगी भारत

इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष दस देशों में भारत छठे स्थान पर है। आतंकी घटनाओं में होने वाली मौतों में 1.2 फीसद इजाफे के साथ यह आंकड़ा 416 पहुंच गया है। 2010 के बाद आतंकी हमलों और मौतों की यह सर्वाधिक संख्या है।

32,658
दुनिया भर में 2014 के दौरान आतंकी हमलों में मारे गए लोग

विस्थापन और पलायन
आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित 11 में से 10 देशों में शरणार्थी और आंतरिक विस्थापन की दर सर्वाधिक

13.4%
आतंकी हिंसा के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगने वाली चपत

2 गुना: ऐसे देशों की संख्या जहां आतंकी घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या 500 से अधिक है, 2013 में पांच से बढ़कर 2014 में 11 हो चुकी है।

52.9 अरब डॉलर: 2014 में आतंकी घटनाओं के चलते दुनिया को लगी चपत। यह उससे पिछले साल के नुकसान 32.9 अरब डॉलर से 61 फीसद अधिक

9 गुना: दुनिया भर में आतंकी हमलों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या में पिछले 15 साल में हुई वृद्धि

80% 2014 में विश्व भर में आतंकी गतिविधियों में दर्ज की गई वृद्धि

हमलों का असर

कोई भी आतंकी घटना लंबे समय के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपना व्यापक असर छोड़ती है। तात्कालिक नुकसान के इतर इस दीर्घकालिक प्रभाव के तहत लोगों में अवसाद घर कर जाता है। सामाजिक वैमनस्य बढ़ता है। राजनीतिक असर के रूप में नियम कानून कठोर किए जाने से विभिन्न देशों के बीच रिश्तों पर असर पड़ते हैं।

अप्रत्यक्ष असर

- उपभोक्ताओं और कंपनियों के भविष्य की अपेक्षाओं को कुंद करते हैं
- सुरक्षा उपायों पर भारी निवेश से देश की कार्यकुशलता पर नकारात्मक असर
- अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वालों (उपभोक्ताओं, निवेशकों और कारोबारियों) की सोच में बदलाव दिख सकता है। लोग भौगोलिक क्षेत्र कतराने पर विवश हो सकते हैं।
- व्यापक भूराजनीतिक संघर्ष की शुरुआत की वजह बन सकते हैं। आर्थिक अवरोध गहराता है।

केस स्टडी

9/11 हमला

अमेरिका पर 9 सितंबर 2001 को हुआ आतंकी हमला सबसे बड़ा, विनाशकारी और सर्वाधिक योजनाबद्ध था। आतंक के असर का आकलन करने के लिए कई विशेषज्ञ इसे अपनी केस स्टडी बना चुके हैं।

नुकसान

तात्कालिक: 11 सितंबर को हुए आतंकी हमले में भौतिक पूंजी के रूप में 15 .5 अरब डॉलर की क्षति हुई। व्यापक आर्थिक असर के रूप में अमेरिकी कंज्यूमर कांफिडेंस इंडेक्स अगस्त, 2011 में 114 अंकों से गिरकर सितंबर में 97 .6 और अक्टूबर में 85 .5 पर पहुंच गया। सितंबर की तुलना में अक्टूबर के दौरान बेरोजगारी दर में 0 .6 फीसद का इजाफा दिखा। पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में साठ हजार नौकरियों का नुकसान हुआ। अनिश्चितता की स्थिति ने कई कारोबार में नई नौकरियों के सृजन और निवेश को रोक दिया। समग्र उत्पादकता पर असर दिखा। विमानन, बीमा, बैंकिंग और यात्रा जैसे क्षेत्रों में कारोबार करने के लिए सुरक्षा के मद में एक और लागत बढ़ी। कई कंपनियों को अतिरिक्त सतर्कता के चलते अपनी सूचना प्रणाली और डाटा को सुरक्षित रखने के एवज में अधिक खर्च करना पड़ा। कारोबार में अनुत्पादक खर्चों का बोझ बढ़ा।

दीर्घकालिक: पहले से ही मंदी की चपेट में चल रहे अमेरिका की स्थिति को गहराने में इस हमले ने अहम भूमिका निभाई। चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी हिस्सेदारी अमेरिका निभाता है लिहाजा इस असर से वैश्विक अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं रही। 9/11 के बाद रक्षा बजट में वृद्धि ने अमेरिकी वित्तीय संकट में इजाफा किया।

एकजुटता से मिलेगी कामयाबी

पेरिस आतंकी हमले के तत्काल बाद आयोजित जी-20 देशों की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'दुनिया को एक सुर में बोलते हुए बिना राजनीतिक विचार किए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई करनी चाहिए।' साथ ही उन्होंने जोड़ा, 'हमें उनको अलग करना चाहिए जो आतंकवाद को समर्थन और प्रायोजित करते हैं और उनके साथ खड़े होना चाहिए जो हमारे मानवता के मूल्यों को साझा करते हैं।'

भारत के सख्त संदेश का मकसद स्पष्ट रूप से एकजुट कार्रवाई से ताकत हासिल करने की जरूरत से है। स्पष्ट है कि फ्रांस या अमेरिका में आतंकी कार्रवाई के बाद जो दुनिया में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, वैसी पाकिस्तान द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ नहीं उत्पन्न होती। ऐसे में प्रधानमंत्री के बयान का अंतरराष्ट्रीय संदेश तो स्पष्ट है लेकिन ठीक इसी तरह भारत में आतंकवाद के मसले पर विविध किंतु दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बांटने वाले विचारों को भी समझना चाहिए। पेरिस आतंकी हमले के बाद यह स्पष्ट हुआ है। एक ओर जहां फ्रांस में सुरक्षा के मसले पर अलग मत रखने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने उन मतभेदों को दरकिनार करते हुए देश के समक्ष आतंकवाद के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत की विभिन्न पार्टियां इस हमलों को एक्शन का एिक्वशन कह रही हैं। पश्चिम में उत्पन्न 'एंटी-इस्लाम फोबिया' को भी इस हमले से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बयान उस भारत देश में आ रहे हैं जोकि दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। यह स्पष्ट रूप से आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय संकल्प की कमी की तरफ संकेत करता है। लोकतंत्र के लिए जरूरी बौद्धिक मतांतरों के बावजूद आतंकवाद के खिलाफ मुहिम प्रभावित नहीं होनी चाहिए लेकिन सामाजिक दरारों का दोहन करते हुए इसे पोषित किया जाता है।

भारत में आतंकवाद के मसले पर बांटने वाले राजनीतिक विचार दुखद हैं। ये स्थिति आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय संकल्प की कमी की द्योतक है।

धर्म, क्षेत्र, जातीयता और राजनीतिक झुकावों के रंग में आतंकवाद को रंग रूप देने की प्रवृत्ति ने दुनिया को संकीर्ण अदूरदर्शी क्षेत्रीय खांचों में बांट दिया है। दुर्भाग्यवश देश में भी इसका खतरा देखने को मिलता है। यद्यपि राष्ट्रीय भावना स्पष्ट दिखती है कि आतंकवाद को किसी भी वजह से तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानमंत्री के हालिया बयानों को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के उस संदर्भ में देखना चाहिए जब संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसले पर भारत का पक्ष रखने के लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। संयोग से उनके साथ सलमान खुर्शीद और फारुख अब्दुल्ला भी गए थे। उस राष्ट्रीय और राजनीतिक एकता का पाकिस्तान सामना नहीं कर पाया और भारत को कूटनीतिक कामयाबी मिली। यह याद रखना चाहिए कि उस टीम के हर सदस्य का विभिन्न मुद्दों पर अपना नजरिया था। वे देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि थे। यद्यपि उनको एकता विविधता से अधिक महत्वपूर्ण थी और उसे आज याद रखने की जरूरत है।

आज आतंकवाद तेजी से वैश्विक रूप से जटिल रूप लेता जा रहा है। इस वैश्विक दुनिया में आतंकी सीमाओं को बेमानी बनाने की कला में माहिर हो गए हैं। इस तथ्य के बावजूद कि वे विभिन्न राष्ट्रों और संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसने खतरे और चुनौतियों को और भी गंभीर कर दिया है। इन परिस्थितियों में कोई भी देश आतंकवाद से तब तक नहीं लड़ सकता जब तक कि राज्य की हर इकाई एक साथ मिलकर काम नहीं करेगी।

-कर्नल विवेक चड्ढा (रिटायर्ड)
(रिसर्च फेलो, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, नई दिल्ली)

आपकी आवाज

भारत तो सदा मानवता और इंसानियत पर भरोसा रखता है इसलिए भारत का साथ आना तो लाजमी है। - **आशीष गुप्ता**

यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इसमें वोट बटोरने और राजनीतिक लाभ लेने जैसा लालच साफ दिख रहा है। - **अमन कुमार**

आतंकवाद दुनिया की नाक में दम करके रखा है। आतंकवाद का काला छाया विश्व में से तभी हट सकता है जब देश इसके खिलाफ एकजुट होकर प्राथमिक तौर पर कड़ा रुख अपनाएंगे। - **राजेश चौहान**

आजम खां का बयान भी आतंकवाद से कम नहीं है। इस तरह के बयानों को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। - **विष्णुकांत शुक्ला**

नहीं, भारत के इस लड़ाई में शामिल होने से सैन्य शक्ति का वितरण होगा। साथ ही निश्चित रूप से यह आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के लिए खतरे मोल लेना होगा। - **मधुराज कुमार**

दोहरे रवैये से वैश्विक मुहिम पड़ चुकी कुंद

-अजय साहनी
(निदेशक, इस्टीट्यूट ऑफ कांफ्लिक्ट मैनेजमेंट)

पेरिस आतंकी हमले के बाद एक बार फिर अभ्यस्त रूप से राजनीतिक एकजुटता देखने को मिली और इस बात की शायद ही गुंजायश है कि पिछले बड़े आतंकी हमलों की तरह 'विश्व शक्तियों' पर इसका भी कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देश पहले की तरह आतंक के एक समूह का समर्थन करते रहेंगे और दूसरे के खिलाफ मोर्चे पर डटे रहेंगे। इसके साथ ही आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजक देश 'दुनिया की एकमात्र महाशक्ति' अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के हल्के नजरअंदाज या सक्रिय साझेदारी के साथ पोषित होते रहेंगे।

पेरिस घटना के बाद एकत्र हुए वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। उन्होंने उसके बाद अपने पहले बयान में भारतीय चिंता प्रकट करते हुए और पाकिस्तान की तरफ परोक्ष इशारा करते हुए एकदम सही कहा कि कुछ देश आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बनाकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में भारत के संकल्प को दोहराते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मुहिम में एकजुट होने का आहवान किया।

यदि अतीत के अनुभवों के आधार पर आकलन किया जाए तो कोई बहुत उम्मीद नहीं दिखती। यहां तक कि दशकों के सतत आतंकवाद ने भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान पर बहुत खास असर नहीं डाला और आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में अड़ंगा ही लगता रहा। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के बाद बड़े-बड़े वादों और नीतिगत घोषणाओं के बावजूद सुरक्षा और खुफिया तंत्र के सुधार के स्तर पर कुछ ठोस नहीं हो पाया और पहले की तरह खतरा बरकरार है। हालांकि ऊपरी स्तर पर कुछ प्रोजेक्ट क्रियान्वित किए गए लेकिन पुलिस तंत्र में बुनियादी खामियां, त्वरित जवाबी कार्रवाई क्षमता, खुफिया क्षमता, टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल क्षेत्रों में कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नियमित ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाए और सक्षम समन्वय के अभाव में अप्रभावी साबित हुए और कई प्रोजेक्ट तो रुक गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स और संबंधित नेशनल डाटाबेस ऑन क्राइम एंड टेररिज्म हैं जो 2009 से ही निस्तेज अवस्था में हैं। मोदी सरकार के आने के बाद केंद्र ने इस मसले पर पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। हर आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान में पश्चिमी देशों की संस्थाओं और उनकी 'बेहतर कार्रवाईयों' से सीखने के संबंध में काफी हो-हल्ला मचता है। 'कम्यूनिटी पोलिसिंग' 'डि-रेडिकेलाइजेशन' 'स्वात रिस्पांस' और नेशनल काउंटर-टेररिज्म सेंटर के बारे में बहुत बातें होती हैं।

वास्तव में हम पश्चिम से सबसे बढ़िया यह पाठ सीख सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। यदि पश्चिम आज इस्लामिक आतंकवाद की गिरफ्त में है तो इसके लिए उसको खुद की नीतियों और कार्रवाईयों को दोषी ठहराना चाहिए। यद्यपि हम पश्चिम से जवाबी कार्रवाई के संबंध में कुछ टेक्नोलॉजी ले सकते हैं लेकिन यदि किसी मॉडल पर हमें ध्यान और रिसर्च करने की जरूरत है तो वह अपनी सारी खामियों के साथ भारतीय मॉडल ही है। हमें ऐसे दौर में अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है जब पश्चिमी देशों की छोटी सी मुस्लिम आबादी में से सैकड़ों-हजारों युवा जिहादी बनने के लिए इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने जा रहे हैं और इसके उलट भारत दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्कों की श्रेणी में शुमार होने और पड़ोसी देश के इस्लामिक आतंकवाद को लगातार उकसाने के बावजूद भारतीय मुसलमानों ने आतंकवाद का भरपूर विरोध किया है। भारत ने कई मोर्चों पर आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में सफलता पाई है लेकिन इनको नजरअंदाज किया गया है और इस मसले पर हरेक की अपनी थ्योरी (विचारधारा और दलगत आधार पर) है। इस अनुभव की कोई राष्ट्रीय स्तर पर सर्वसम्मति नहीं है। नतीजतन इस अनुभव को अन्य मोर्चों पर हस्तांतरित करने की क्षमता नहीं है।

'आतंकवाद के खिलाफ' एकजुटता का नारा बारंबार छला गया। इसके खिलाफ वैश्विक प्रतिबद्धता अपने 'राष्ट्र हितों' की आड़ में हाशिए पर धकेल दी गई। आतंक के खिलाफ रणनीतिक खामियां प्रमाण के तौर पर हर जगह मौजूद हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामिक स्टेट को निश्चित रूप से हराया जाएगा। लेकिन इसको पैदा करने वाली वैश्विक समस्याओं का अंत नहीं होगा और आतंकवाद का खतरा आसानी से किसी अन्य रूप और पहचान में रूपांतरित हो जाएगा। भारत अपेक्षाकृत इस्लामिक स्टेट के आतंक से अछूता है लेकिन भले ही इस्लामिक आतंकवाद का यह खतरा मौजूदा परिदृश्य में सीमित स्तर पर दिखता हो लेकिन यह बहुत अहमियत रखता है और भारत इससे मुकाबला करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है।

जनमत

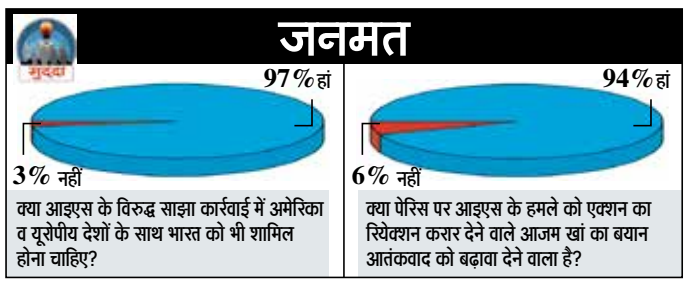

क्या आइएस के विरुद्ध साझा कार्रवाई में अमेरिका व यूरोपीय देशों के साथ भारत को भी शामिल होना चाहिए?

क्या पेरिस पर आइएस के हमले को एक्शन का रियेक्शन करार देने वाले आजम खां का बयान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है?

विषबेल की खुराक

सीआइए के एक अनुमान के मुताबिक अलकायदा हर साल अपनी आतंकी गतिविधियों पर 3 करोड़ डॉलर की रकम खर्च करता है। आए दिन होने वाले आतंकी हमलों के आगाज से लेकर अंजाम तक आइएस जैसे आतंकी संगठन करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह ही इनका सालाना बजट होता है। किस मद में कितना खर्चा किया जाना है, यह सब पूर्व नियोजित होता है। जाहिए है इस सबके लिए इनको भारी मात्रा में धन की जरूरत होती है।

वित्तीय स्रोत

आपराधिक गतिविधियां मसलन बैंक डकैती, अपहरण, वसूली, तस्करी और ड्रग्स का अवैध धंधा

चंदा: आतंकी संगठनों को सऊदी अरब, कुवैत, कतर और संयुक्त राज्य अमीरात (यूएई) के धनी लोगों एवं वहां की चैरिटी संस्थाओं द्वारा काफी धन प्राप्त होता है। इसके अलावा देशी /विदेशी लोगों और चैरिटी संस्थाओं और आतंकवाद से सहानुभूति रखने वाले देशों से इनको आर्थिक मदद मिलती है

हवाला चैनल: धन एकत्र करने में हवाला भी एक स्रोत है

मादक पदार्थों की तस्करी: यह धन प्राप्ति का प्रमुख जरिया है।

मनीलॉड्रिंग: एक आकलन के अनुसार हर साल करीब एक ट्रिलियन डॉलर की मनी लॉड्रिंग होती है।

तेल का कारोबार: सीरिया और इराक में अपने कब्जे वाले क्षेत्रों के तेल स्रोत आइएस जैसे संगठनों का मुख्य वित्तीय जरिया हैं।

आतंकी खर्च

- 9/11 को अंजाम देने में अलकायदा ने पांच मिलियन डॉलर (बीस करोड़ रुपये से अधिक) खर्च किए
- 2002 में बाली के एक नाइटक्लब में विस्फोट करने के लिए आतंकियों ने करीब 50 हजार डॉलर खर्च किए थे
- स्पेन के मैड्रिड बम विस्फोट को अंजाम देने में आतंकियों का खर्च 10,000-15,000 हजार डॉलर आया था
- वर्ष 2005 में लंदन में हुए एक बम विस्फोट में आतंकियों ने 2,000 डॉलर खर्च किया था